भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2785

उत्तर देने की तारीख 20 दिसम्बर, 2023

टेलीफोन कनेक्शन

2785. श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री सत्यदेव पचौरी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या में हुई वृद्धि से संबंधित आंकड़ों का जिला-वार और हरियाणा के सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की उपलब्धता में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में किसी वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) पिछले 10 वर्षों में हरियाणा लाइसेंस सेवा क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है:

क्र. सं.	पैरामीटर	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
1	बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस)	14,709	56,703
2	बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) (किमी)(राज्य)	29,315	78,303

3	भारतनेट सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतें (जीपी)(राज्य)	शून्य	6,082
4	टेलीफोन कनेक्शन्स	2.18 करोड़	2.71 करोड़
5	इंटरनेट उपभोक्ता	54.0 लाख	190 लाख
6	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	10.4 लाख	182 लाख

(ख) से (ग) देश में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या में भी काफी सुधार हुआ है जो कि नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	पैरामीटर	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
1	इंटरनेट उपभोक्ता	25.16 करोड़	88.12 करोड़
2	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	6.09 करोड़	84.66 करोड़

सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(I) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, नकद निवेश करने, निवेश को प्रोत्साहित करने, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) पर विनियामक बोझ को कम करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार कार्यान्वित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

(i) समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाना।

(ii) स्पेक्ट्रम को साझा करने, स्पेक्ट्रम का व्यापार करने और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) को युक्तिसंगत बनाने जैसे स्पेक्ट्रम संबंधी सुधार।

(iii) स्पेक्ट्रम को साझा करने के लिए प्रोत्साहन देना।

(iv) खुली और पारदर्शी नीलामी के माध्यम से पर्याप्त स्पेक्ट्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(v) सुरक्षा उपायों के अध्ययधीन आटोमेटिक रूट के अंतगर्त दूरसंचार क्षेत्र में 100 % प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए अनुमति।

(vi) मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) के शीघ्र अनुमोदन के लिए पीएम गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ।

(vii) भारतीय तार मार्गाधिकार नियमावली 2016 और दूरसंचार अवसंरचना के अधिक तीव्र और आसान रोल आउट के लिए समय-समय पर संशोधन नियम जारी करना।

(viii) 'रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति' (एसएसीएफए) द्वारा दूरसंचार टावरों के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया को काफी आसान बनाया गया है।

(II) उपर्युक्त के अतिरिक्त:

- भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध ढंग से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का उपयोग करके किया जा रहा है। दिनांक 13.11.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत कुल 2,07,346 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा, दिनांक 04.08.2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट के कार्य-क्षेत्र को ग्राम पंचायतों (जीपी) से आगे बढ़ाकर सभी बसे हुए गांवों तक करने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम अनुमोदित कर दिया है।
- आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों और सेवा से वंचित/सेवा की कम उपलब्धता वाले अन्य क्षेत्रों सहित देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए यूएसओएफ के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी), द्वीपसमूहों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना सहित विभिन्न परियोजनाओं और मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है।
- देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 26,316 करोड़ रूपए की कुल लागत से देशभर के सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं के सेचुरेशन के लिए परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए ''पूंजी निवेश 2022-23 के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम'' नामक स्कीम लॉन्च की है। ऑप्टिकल फाइबर केबल संबंधी पूंजीगत परियोजनाओं के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई गई है और 24 राज्यों के संबंध में 2716 करोड़ रूपए की राशि की परियोजनाओं के लिए अनुमोदन दिया गया है।
- देश के ग्रामीण/सुदूर/सेवा से वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं/इंटरनेट सेवाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न यूएसओएफ परियोजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के दौरान 19,000 करोड़ रूपए संवितरित किए गए हैं।

परिणामस्वरूप, 738 जिलों में 3.99 लाख बेस ट्रांसीवर्स स्टेशन (बीटीएस) स्थापित कर, भारत ने विश्व में 5जी सेवाओं का तीव्रतम रोलआउट किया है। मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए मीडियन गति भी मार्च 2014 में 1.30 मेगाबिट्स प्रति सेकंड (एमबीपीएस) से बढ़कर अक्टूबर, 2023 में 75.80 एमबीपीएस हो गई है।

दूरसंचार क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक रहा है। दूरसंचार क्षेत्र ने वर्ष 2004-14 की अवधि में 12.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2014-2023 की अवधि में 24.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त की है।

*****